सत्यमेव जयते

श्री ओम प्रकाश कोहली

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

10 फाल्गुन, 1938 शक भोपाल, मंगलवार, 21 फरवरी 2017

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधान सभा के इस चौथे बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है।

2. मेरी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिये कृत संकल्पित है। इसी के दृष्टिगत सरकार ने हर वर्ग को सीधे लाभ पहुँचाने की योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये हैं। वर्ष 2017 पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती का वर्ष है और मेरी सरकार इसे गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इस वर्ष समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के प्रयासों को और बढ़ाया जायेगा। रोटी, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार के साधन प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को मिले, यह मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी।

3. मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कल्पनाशील नेतृत्व में देश के विकास में योगदान देने के लिये तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, किसानों की आय को पाँच साल में दोगुना करने के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं, मुद्रा योजना, ईज ऑफ डूईंग, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, सबके लिये आवास, स्मार्ट सिटी योजना और सबसे बढ़कर डिजिटल इकॉनामी बनाने के क्षेत्र में प्रदेश सरकार संकल्पवान होकर काम कर रही है।

4. जनवरी 2016 में प्रदेश के कुछ जिलों में ओला वृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार ने सभी प्रभावितों को तत्काल राहत पहुँचायी। आगे भी सरकार हर आपदा में किसानों और सभी लोगों के साथ खड़ी रहेगी।

5. मेरी सरकार द्वारा सभी भुगतान कैशलेस माध्यम से किये जा रहे हैं। प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों का भी लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। व्यापारियों को पी.ओ.एस. मशीन खरीदने पर वेट टैक्स पर एवं मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार ने डिजीटल भुगतान मिशन चलाने का निर्णय लिया है।

6. मेरी सरकार द्वारा केन्द्रीयकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इस प्रणाली से राज्य की सभी गतिविधियाँ, मानव संसाधन एवं जनसेवा कार्य पूरी तरह ऑन लाईन और पेपरलेस हो जायेंगे।

7. मेरी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर 16.62 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

8. मेरी सरकार की खेती को लाभदायी बनाने की कोशिशें परिणाम दे रही हैं। चार वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर औसतन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश दलहन, तिलहन, चना, मसूर, सोयाबीन, लहसुन एवं टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश को भारत सरकार द्वारा लगातार 4 वर्ष से कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्रीजी के आव्हान पर सरकार ने किसानों की आय पाँच वर्षों में दोगुनी करने का रोडमेप सबसे पहले बनाकर तेजी से अमल शुरू कर दिया है।

9. इस वर्ष खरीफ में 236 लाख मी. टन फसलों के उत्पादन का अनुमान है। यह प्रदेश के इतिहास में खरीफ का सर्वाधिक उत्पादन है। रबी का क्षेत्राच्छादन 117 लाख हेक्टेयर में हुआ है, जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। गेहूँ उत्पादन इस वर्ष दो करोड़ मी. टन संभावित है। मेरी सरकार इस वर्ष पुनः कृषि महोत्सव का आयोजन कर किसानों की आय दुगुना करने के लक्ष्य को जन आंदोलन का स्वरूप देगी।

10. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2015 के लिये 20 लाख 47 हजार किसानों को देश के इतिहास की सबसे ज्यादा 4416 करोड़ की फसल बीमा दावा राशि वितरित की गई। पिछले एक वर्ष में प्रदेश के किसानों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु 18,444 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में मेरी सरकार ने उपलब्ध कराई है। पहली बार चार लाख से अधिक अऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़े गये।

11. कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों की आसान खरीद के लिये ऑनलाईन पंजीयन शुरू किया गया है। किसानों को फसल प्रदर्शनों में बीज को छोड़कर शेष आदान स्वयं क्रय करने की सुविधा दी गई है। सामग्र पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खात में जमा करने की योजना का लाभ 2 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है।

12. कृषि वानिकी ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके विस्तार से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि में जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। अत: मेरी सरकार ने कृषि वानिकी मिशन के रूप में एक नया मिशन चलाने का निर्णय लिया है।

13. भोपाल की करोंद कृषि उपज मण्डी सहित प्रदेश की 21 कृषि मण्डी राष्ट्रीय कृषि मण्डी योजना से जुड़ गई हैं। इस वित्त वर्ष में 30 और मण्डियों को योजना से जोड़ा जायेगा। सभी जिलों में कृषि उपज मण्डियों में फल-सब्जी के लिये आधुनिक प्लेटफार्म, क्लीनिंग-ग्रेडिंग-पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज/चेम्बर स्थापित किये जायेंगे।

14. मेरी सरकार के उपक्रम से पिछले 11 वर्षों में उद्यानिकी फसलों का रकबा 5 लाख से बढ़कर साढ़े 14 लाख हेक्टेयर हो गया है। अगले 5 साल में उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार में कलस्टर आधारित 50 प्रतिशत और उत्पादकता में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन एवं विपणन की समुचित व्यवस्था की गयी है। खेत से मण्डी तक कोल्ड चेन की स्थापना और माइक्रो ईरीगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी सेवाओं को ऑन-लाईन किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार पशुधन के संरक्षण-संवर्द्धन के लिये निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2015-16 में देश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 6.27 की तुलना में प्रदेश की वृद्धि दर 12.70 प्रतिशत रही है। यह वृद्धि दर प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में सर्वाधिक है। इस अवधि में प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 428 ग्राम प्रतिदिन रही, जो राष्ट्रीय औसत 337 से अधिक है। सरकार ने इस वर्ष से आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना शुरू कर एक परिवार को 5 गाएं देने का प्रावधान किया है। योजना में प्रति पशुपालक 10 लाख रुपये तक की डेयरी इकाई के लिये 17 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

16. सरकार ने बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर का गठन किया है। एक हजार से ज्यादा दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को बैंक के माध्यम से भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है। सागर, शिवपुरी और कीरतपुर में 100 मी. टन प्रतिदिन क्षमता के पशु आहार संयंत्र स्थापित किये गये हैं। इस वित्त वर्ष में 269 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। कीरतपुर जिला होशंगाबाद में राष्ट्रीय कामधेनु बीडिंग सेन्टर स्थापित किया जा रहा है।

17. मेरी सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा दिया है। कुल उपलब्ध जल क्षेत्र के 98 प्रतिशत में मत्स्य-पालन हो रहा है। दृष्टि-पत्र 2018 में 100 करोड़ मत्स्य-बीज उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति इसी वर्ष 107 करोड़ मत्स्य-बीज उत्पादन से कर ली गई है। नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुव्यवस्थित मत्स्य-विक्रय के लिये 136 छोटे मछली बाजारों का निर्माण किया गया है।

18. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली दी जा रही है। उपलब्ध बिजली क्षमता 17 हजार 412 मेगावॉट है, जिसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 22 हजार मेगावॉट से अधिक किया जाएगा। इस वर्ष 611 मेगावॉट की वृद्धि की गई है।

19. इस वर्ष से लागू ''मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना'' में जून 2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शन को स्थाई में बदला जायेगा। इस वर्ष एक लाख तीन हजार स्थायी पम्प कनेक्शन दिए गए हैं।

20. प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का प्रतिशत 2.88 के स्तर पर आ गया है। सरकार वितरण हानियों में प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिये प्रयासरत है। ''उदय'' योजना में विद्युत वितरण कम्पनियों के 26 हजार करोड़ से ज्यादा के ऋण को चरणबद्ध अंशपूँजी और अनुदान में बदला जायेगा।

21. मेरी सरकार द्वारा किसानों को मात्र 1400 रुपये प्रति हार्स पावर सालाना की दर से बिजली दी जा रही है। सरकार द्वारा पाँच हार्स पावर तक के एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इन पर पिछले वर्ष 6717 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई ।

22. नवकरणीय ऊर्जा की इस वर्ष स्थापित क्षमता की दृष्टि से प्रदेश देश में प्रथम रहा है। इस वर्ष देश की लगभग 24 प्रतिशत क्षमता प्रदेश में स्थापित हुई। अब प्रदेश की क्षमता 3019 मेगावाट हो गयी है। इस वर्ष देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में प्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत रही है। रीवा जिले में 4500 करोड़ की लागत की 750 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। विश्व में सबसे बड़ी सोलर इकाई के रूप में स्थापित होने वाले इस प्लांट के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाईन नीलामी की थी उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली और देश में सबसे कम रुपये 2.97 प्रति यूनिट की दर प्राप्त हुई है।

23. उजाला योजना में प्रदेश में दिसम्बर अंत तक एक करोड़ से अधिक एल.ई.डी. बल्ब का वितरण हुआ है।

इससे सालाना 1825 मिलियन यूनिट्स बिजली की बचत होगी और उपभोक्ताओं के बिल में सालाना 1095 करोड़ की कमी आयेगी।

24. मेरी सरकार ने दृष्टि-पत्र 2018 के लक्ष्य के अनुरूप 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया है। जिसमें नर्मदा घाटी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित साढ़े पांच लाख हैक्टेयर रकबा सम्मिलित है। वर्ष 2025 तक शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर करने की कार्य-योजना पर कार्य किया जा रहा है।

25. सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में गत वर्ष 6,607 करोड़ का निवेश किया गया। इस वर्ष 9,313 करोड़ रुपये निवेश किये जा रहे हैं। दृष्टि-पत्र 2018 में 700 लघु सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 646 परियोजनाएँ पूर्ण कर ली गई है। वर्तमान में 18 वृहद्, 36 मध्यम एवं 407 लघु सिंचाई परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है।

26. सरकार द्वारा वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों से हो रही सीपेज क्षति को रोकने के लिये लाइनिंग कार्य कराया जा रहा है। अब तक 13,500 कि.मी. लम्बाई में लाइनिंग की जा चुकी है। बालाघाट जिले की वर्ष 1914 में निर्मित वैनगंगा वृहद् परियोजना के सौ वर्ष पूरे होने पर नहरों की लाइनिंग कार्य शुरू कर 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

27. सरकार ने सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। इसमें किसानों को प्रत्येक ढाई हेक्टेयर रकबे तक पाईप लाईन द्वारा दाबयुक्त नर्मदा जल वितरण पद्धति निर्मित करने की पहल की है। इससे किसान फौव्वारा एवं ड्रिप पद्धति से उपलब्ध जल का शत-प्रतिशत उपयोग कर सकेंगे। इस हेतु राजगढ़ जिले की मोहनपुरा और कुण्डबिया, टीकमगढ़ जिले की वानसुजारा और छिन्दवाड़ा जिले की पेंच वृहद् परियोजना का काम तेजी से जारी है। उसी प्रकार नर्मदा घाटी परियोजनाओं में नर्मदा, मालवा, गंभीर लिंक, बलवाड़ा छैगांव माखन और विष्टान का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष चंदेरी जिला अशोकनगर, गरोठ जिला मंदसौर, नईगढ़ी, जिला रीवा एवं रामनगर जिला सतना की वृहद् माइक्रो इरीगेशन परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं।

28. माइक्रो इरीगेशन परियोजनाओं का सभी किसानों को पूरा लाभ मिले, इस हेतु मेरी सरकार ने माइक्रो इरीगेशन मिशन चलाने का निर्णय लिया है। मिशन इन परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और अन्य माइक्रो इरीगेशन के साधन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

29. केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दोधन बांध, लोअर ओर परियोजना, बीना कांप्लेक्स व कोठा बैराज की वैधानिक स्वीकृतियों की कार्यवाही काफी आगे बढ़ गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन निकट भविष्य में प्रारंभ किया जाना संभावित है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश में 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभावित है।

30. नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना की सफलता ने देश में पहचान बनायी है। योजना से क्षिप्रा नदी प्रवाहमान हुई और सिंहस्थ के स्नान पर्वों पर भरपूर जल सुलभ हुआ।

31. खेती-किसानी को लाभकारी बनाने में सहकारिता क्षेत्र का महती योगदान है। इस वर्ष दिसम्बर तक किसानों को 9762 करोड़ 63 लाख का फसल ऋण शून्य ब्याज दर पर वितरित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 15 हजार करोड़ के अल्पावधि फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। सहकारी समितियों द्वारा 53 लाख 12 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 तक प्रतिवर्ष 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य है।

32. अब मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में खाद एवं बीज के लिये दिये गये वस्तु ऋण की राशि पर 10 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपये सालाना का अनुदान सरकार द्वारा देय होगा।

33. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रदेश में प्याज के अधिक उत्पादन तथा घटती कीमत को देखते हुए किसानों द्वारा उत्पादित प्याज की खरीदी की गई। व्यापारी/बिचौलियों से बचाते हुए 41 हजार 482 किसानों से 10 लाख क्विंटल से ज्यादा प्याज 62 करोड़ 42 लाख के व्यय से खरीदकर उन्हें राहत दी गई।

34. प्रत्येक किसान को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक किसान को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने के सदस्यता इस अभियान में 10 लाख 76 हजार किसानों को सहकारिता से जोड़ा गया है। 19 पर्यटन, 10 परिवहन, 28 रहवासी एवं 9 ई-रिक्शा परिवहन और 17 जैविक कृषि सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं। दो सेवा प्रदाता सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की गई है।

35. सहकारिता विभाग ने ''सहकारिता मंथन'' के आयोजन द्वारा सहकारिता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में विद्यमान सहकारी आयामों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के नवाचार स्थापित करने का विस्तृत कार्यक्रम चलाया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे।

36. मेरी सरकार प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क सुधारने के लिये व्यापक प्रयास कर रही है। लगभग 5500 कि.मी. नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई जिसमें से 3025 कि.मी. एनएच मंजूर किये जा चुके हैं। 2383 कि.मी. नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांकित स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार 3778 कि.मी. नये राजमार्ग और 4211 कि.मी. नये मुख्य जिला मार्ग घोषित किये गये हैं। पिछले वर्ष 3877 कि.मी. लम्बाई की सड़कों तथा 101 नये बड़े पुलों का निर्माण किया गया है।

37. सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत कराई है जिससे 1529 कि.मी. मुख्य जिला मार्गों का विकास किया जायेगा।

न्यू डेवलपमेंट बैंक से पहल करते हुए मेरी सरकार ने 500 मिलियन डॉलर के नये प्रोजेक्ट स्वीकृत कराए हैं जिससे 1502 कि.मी. नये मुख्य जिला मार्गों का निर्माण कराया जायेगा। प्रदेश अधोसंरचना निर्माण के लिये न्यू डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला राज्य है।

38. सरकार ने उच्च गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बनाने के लिये सीमेंट-कांक्रीट की सड़कें बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक 5500 कि.मी. सीमेंट-कांक्रीट सड़क बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

39. मेरी सरकार गाँवों के चौतरफा विकास के लिये पूरी क्षमता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 3 हजार 935 कि.मी. लम्बाई के 787 मार्गों के निर्माण से 787 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्क सुविधा मिली है। योजना प्रारंभ से अब तक 64 हजार 656 कि.मी. लंबाई की 15 हजार 545 सड़कों तथा 138 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। अगले वर्ष 5 हजार कि.मी. सड़कों का उन्नयन एवं निर्माण किया जायेगा।

40. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 8 हजार 389 ग्रामों में 18 हजार 365 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनायी जा रही हैं। अब तक 6 हजार 863 ग्रामों में 14 हजार 124 कि.मी. लम्बी सड़कें बन गई हैं। अगले वर्ष इन ग्रेवल सड़कों को डामरीकृत करने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

41. मेरी सरकार गरीब आवासहीन परिवारों को भूखण्ड या आवास उपलब्ध कराने के लिये कानूनी प्रावधान करने जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक आवासीय इकाईयों का निर्माण देश में मेरी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रदेश में कोई भी आवासहीन रहे, इस हेतु आवास मिशन चलाया जाएगा। मिशन के तहत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख और नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख इस प्रकार 20 लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

42. स्वच्छ भारत मिशन में 02 अक्टूबर 2019 तक सभी 22 हजार 825 ग्राम पंचायतें एवं 54 हजार 903 ग्रामों के 122 लाख घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

जनवरी 2017 तक 13 लाख घरों में शौचालय उपलब्ध कराये गये हैं। अभी तक दो जिले इन्दौर एवं हरदा एवं अन्य जिलों में 6 विकासखण्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गये हैं।

43. मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 33 जिलों में क्रियान्वित है। मिशन के प्रारंभ से 19 लाख 45 हजार परिवारों को एक लाख 65 हजार से ज्यादा स्व-सहायता समूहों से जोड़कर बैंकों से एक हजार 351 करोड़ का ऋण दिलाया गया है। प्रारंभ से अब तक 5 लाख 46 हजार ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों से रोजगार सुलभ कराए गए हैं।

44. वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 14 हजार 114 छोटे उद्यमियों को 91 करोड़ से ज्यादा का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष साढ़े 3 लाख परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया। अब तक 12 लाख 85 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।

45. ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत इस वर्ष अब तक रुपये 2292 करोड़ 46 लाख की राशि दी गई है। इस वर्ष पंच-परमेश्वर योजना में सी.सी. सड़कों के निर्माण के लिये 30 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश दिया जायेगा। इस वर्ष भी 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान संचालित किया जायेगा।

46. मेरी सरकार नगरों के सुनियोजित विकास और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश में चालू वर्ष में पेयजल के 19 और सीवरेज प्रबंधन के लिये 16 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। आगामी वर्षों में पेयजल के कुल 141 एवं सीवरेज प्रबंधन के कुल 122 परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना में भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन को शामिल किया है। सागर और सतना के प्रस्ताव भेजे गये हैं। सरकार अपने साधनों से अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कार्य-योजना तैयार कर रही है। प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 34 शहरों का चयन अमृत योजना में हुआ है।

47. सरकार ने सभी नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, यूआईडीएसएसएमटी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमृत, वर्ल्ड बैंक योजनाओं में शामिल किया है।

शहरी विकास के लिये 1428 करोड़ की मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पर अमल हो रहा है। योजना के दूसरे चरण में 1800 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश में 58 शहरों की आवास योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इस वर्ष 31 हजार 838 भवन शहरी गरीबों को आवंटित किये गये हैं।

48. शहरी स्वच्छता के अन्तर्गत 39 नगरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। मार्च 2017 तक प्रदेश के समस्त 378 नगरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने का लक्ष्य है। शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को 26 क्लस्टर में समस्त 378 नगरीय निकायों में लागू किया जाना प्रारंभ किया गया। कचरे से विद्युत् उत्पादन की जबलपुर इकाई में 8 मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

49. ''राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' प्रदेश के 55 शहरों में क्रियान्वित है। इस मिशन के तहत स्वरोजगार और शेल्टर होम बनाने में गत वर्ष हम देश भर में प्रथम स्थान पर रहे हैं। जनवरी, 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना शुरू की गई है। प्रदेश के 20 जिलों में लोक परिवहन व्यवस्था के लिए 351 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। भोपाल एवं इन्दौर की मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

जबलपुर और ग्वालियर की मेट्रो रेल परियोजना की फिजिबिलिटी अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

50. प्रदेश में तीन चरणों में नगर उदय अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में चिन्हित 12 लाख पात्र हितग्राहियों को 8 फरवरी को लाभान्वित किया गया है। यह अभियान प्रतिवर्ष संचालित किया जायेगा।

51. नगरीय क्षेत्र की अति गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चुने हुए नगरों में दीनदयाल थाली योजना लागू करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। इसके तहत गरीबों को 5 रुपये प्रति थाली के मान से स्वादिष्ट और गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध होगा। योजना का विस्तार सभी शहरों में किया जायेगा।

52. मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के कल्याण पर मेरी सरकार प्रदेश में आबादी के समानुपात से अधिक राशि व्यय कर रही है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन वर्गों के कल्याण के लिए एक पांच वर्षीय पैकेज तैयार किया जाएगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बस्ती विकास, आवास, कौशल विकास इत्यादि घटक सम्मिलित रहेंगे।

इन वर्गों की संवैधानिक सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।

53. विभिन्न कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत अब तक अनुसूचित जाति के 2,456 युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में इस वर्ष 6111 युवाओं को 135 करोड़ से ज्यादा की ऋण सहायता दी गई है। सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं का भुगतान ई-पेमेंट से किया जा रहा है।

54. दस संभागीय मुख्यालयों पर ज्ञानोदय विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। इन ज्ञानोदय विद्यालयों में स्पोर्टस काम्पलेक्स भी बनाये जा रहे हैं।

55. इस वर्ष बुरहानपुर और उमरिया में बालक और इटारसी में बालिका क्रीड़ा परिसर के साथ ही 20 नये प्री मेट्रिक, 80 नये पोस्ट मेट्रिक 50 सीटर छात्रावास और 5 नये 50 सीटर आश्रम खोले गये हैं। अगले वर्ष 20 प्री मेट्रिक, 20 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास और 10 नये आश्रम खोले जायेंगे। छात्रावास/आश्रम पालक समितियाँ गठित की गई हैं।

56. अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। तीस हजार विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना का लाभ लिया है। वर्ष 2016-2017 में सैनिक स्कूल प्रवेश छात्रवृत्ति 111 विद्यार्थियों को, प्रदान की गई, सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल 415 विद्यार्थियों को 77 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई एवं दिल्ली में 28 विद्यार्थियों को कोचिंग का लाभ प्रदान किया गया है। कौशल विकास योजना से इस वर्ष दिसम्बर तक करीब चार हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना में 44 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराये गये हैं।

57. वर्ष 2016-17 में सरकार ने 1040 मिडिल स्कूल का हाई स्कूल और 134 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया है। बीस कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किये गये हैं।

58. सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी पात्रताधारी वन निवासी वन अधिकारों से वंचित न रहे। अब तक 2 लाख 38 हजार 381 अधिकार-पत्र बाँटे जा चुके हैं। अधिकार धारकों को कृषि प्रयोजन संबंधी अन्य सुविधाएँ भी दी जा रही हैं।

59. वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के 1893, अनुसूचित जनजाति के 3160 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 1737 कुल 6790 पदों की पूर्ति की गई। विशेष भर्ती अभियान में वर्ष 2015 तक अनुसूचित जाति के 16 हजार 3, अनुसूचित जनजाति के 27 हजार 966 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 11 हजार 54 इस तरह कुल 55 हजार 23 पदों की पूर्ति की जा चुकी है।

60. मेरी सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति सजग है। इस वर्ष पिछड़ा वर्ग के चार लाख से अधिक विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। दो सौ विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति और यूपीएससी/पीएससी की परीक्षाओं में सफल 884 विद्यार्थियों को 147 लाख से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का 2 हजार और कौशल विकास योजना का लाभ 10 हजार परीक्षार्थी को मिला है।

61. प्रदेश के समस्त जिलों में अब तक 100 सीटर बालक और 50 सीटर बालिका छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के लिये भोपाल में 4, श्योपुर, खरगोन एवं बुरहानपुर में एक-एक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। भोपाल में 3 छात्रावास बन भी गये हैं। इन्दौर में 500 सीटर और शाजापुर में 50 सीटर कन्या छात्रावास भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत बन रहे हैं। वर्ष 2016-17 में छात्र गृह योजना से 604 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

62. इस वर्ष 90 हजार से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्री, पोस्ट मेट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति ऑनलाईन दी जा रही है। भोपाल में हज हाउस बन गया है।

63. घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। हाल ही में देवास में राज्य स्तरीय सम्मेलन के जरिए इस वर्ग से जीवंत संपर्क कायम किया गया और उनके विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

64. मेरी सरकार प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करवाने के लिये बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश के गरीब परिवार के मरीजों को दो लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध कराई जायेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर 15 जनवरी से 27 फरवरी की अवधि में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाये जा रहे हैं। शिविरों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की पहचान कर समुचित उपचार सुनिश्चित किया जायेगा. महिला स्वास्थ्य शिविरों में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उपचार की व्यवस्था की जायेगी।

65. प्रदेश की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने की नितांत आवश्यकता है। इसे राष्ट्रीय औसत तक कम करने हेतु मेरी सरकार ने स्वास्थ्य मिशन चलाने का निर्णय लिया है।

66. सभी जिला चिकित्सालयों में अगले वित्तीय वर्ष में ट्रामा सेंटर प्रारम्भ कर दिये जायेंगे एवं प्रदेश के बड़े जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन की सुविधा भी बी.पी.एल. परिवारों के लिये मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी। सरकार ने सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की है। सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर के रोगियों की कीमोथैरेपी के लिये स्टॉफ को प्रशिक्षित कर कैंसर उपचार करवाया जा रहा है। कैंसर से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिये जिला चिकित्सालय उज्जैन में पेलिएटिव केयर इकाई स्थापित की गई है।

67. 108 एंबुलेंस सेवा से 6 लाख, जननी एक्सप्रेस से साढ़े 8 लाख तथा दीनदयाल चलित अस्पतालों से पौने दस लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। अब 108 एंबुलेंस सेवा और जननी एक्सप्रेस को एकीकृत कर दिया गया है। प्रदेश में मलेरिया के प्रकरण में 25 और मलेरिया फेल्सीफेरम में 34 प्रतिशत की कमी आई है।

68. मेरी सरकार के महिला सशक्तिकरण के काम देश में मिसाल बने हैं। इस साल बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी को रोकने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये लालिमा योजना लागू की गई है।

69. प्रदेश में 4305 नयी आँगनवाड़ी तथा 600 मिनी आँगनवाड़ी की स्वीकृति दी गई है। सरकार के प्रयासों से कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2005-06 में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 12.6 था, जो अब घटकर 9.2 रह गया है। कम वजन के बच्चों का प्रतिशत भी 2013-14 के एनएचएसएफ सर्वे में 60 से घटकर 42.8 रह गया है। ''स्नेह सरोकार'' कार्यक्रम में सवा लाख बच्चों का पोषण सुधार उत्तरदायित्व समाज ने लिया है।

70. लाडो अभियान से अभी तक 82 हजार से ज्यादा बाल विवाह समझाइश से रोके गये हैं। अभियान को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार और कॉमनवेल्थ अंतराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। शौर्या दल की सफलताओं को भी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 24 लाख से अधिक बालिकाओं को मिल चुका है।

योजना की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये ई-लाड़ली पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस शिक्षा सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लाड़लियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति ई-पेमेन्ट से दी जा रही है।

71. मेरी सरकार परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के सभी आयुर्वेद चिकित्सालयों में पंचकर्म सुविधा का विस्तार किया गया है। शासकीय होम्योपैथी कॉलेज भोपाल में 07 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं।

72. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथी डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए निर्णय लिया है कि आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को सीमित प्रशिक्षण देकर उन्हें ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किया जाएगा, जहाँ एलोपैथी डॉक्टर का पद रिक्त है।

73. प्रदेश के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में 100 सीटें तथा रीवा में 50 सीटें बढ़ाने की योजनाओं को मंजूरियां दी गई हैं। सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 435 करोड़ 97 लाख की स्वीकृति दी गई है।

चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी सेंटर के लिये 31 करोड़ 88 लाख की राशि मंजूर की गई है।

74. मेरी सरकार शैक्षणिक गुणवत्ता की वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से कर्मी कल्चर को खत्म किया है। संविदा शिक्षकों और अध्यापक संवर्गों को वेतनमान, सुविधाओं सहित उनका सम्मान लौटाया है। इस वर्ष शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक के लगभग 82 लाख पात्र विद्यार्थियों को 8 विभाग की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ, ऑनलाइन स्वीकृत की गईं। लगभग 63 लाख पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण एक साथ एक क्लिक द्वारा किया गया। इस वर्ष 1014 मिडिल का हाई-स्कूल और 100 हाई-स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। अगले सत्र से कक्षा पहली से 7 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान विषयों तथा 9 एवं 11 के लिए विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य विषयों की एनसीआरटी पाठ्य पुस्तकें लागू की जायेंगी।

75. इस वर्ष निःशुल्क साइकिल वितरण से 5 लाख 90 हजार, पाठ्य-पुस्तक वितरण से 95 लाख, गणवेश वितरण से 71 लाख 76 हजार, लेपटॉप वितरण से 17 हजार 896 विद्यार्थी लाभांवित हुए हैं। सुपर 100 योजना में 499 विद्यार्थी को व्यावसायिक कॉलेजों के साथ आई. आई. टी. मेडिकल एवं सी. ए. की कोचिंग दी जा रही है।

शिक्षा का अधिकार कानून का इस वर्ष एक लाख 5 हजार बच्चों को लाभ मिला है। आवासीय व्यवस्थाओं से लगभग 70 हजार छात्राएँ लाभान्वित हो रही हैं। ''रुक जाना नहीं'' योजना में पौने दो लाख अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा की सुविधा देकर 61 हजार विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाया गया है।

76. स्कूलों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु मेरी सरकार ने ''मिल बांचें मध्यप्रदेश'' के नाम से एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें स्वयंसेवी व्यक्तियों ने विद्यालयों में जाकर बच्चों का ज्ञान संवर्द्धन का कार्य किया है। इन स्वयंसेवी व्यक्तियों को शाला से स्थायी रूप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

77. मेरी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा सुविधाओं को निरंतर बढ़ाया जा रहा है. पिछले साल 20 नये कॉलेज खोले गये। वर्ष 2014-15 के प्रवेशित एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिये गये। वर्ष 2015-16 के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किये जा रहे हैं। इक्कीस कॉलेजों के भवन निर्माण के लिये राशि जारी की गई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिये विश्व बैंक से अनुबंध किया गया है। व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ का लाभ एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला है।

78. मेरी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का राष्ट्रीय-स्तर के चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर पूरी फीस वहन करने का फैसला लिया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका 85 प्रतिशत से कम अंक होने पर भी राष्ट्रीय-स्तर के चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों में चयन होता है तो उन्हें सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर गणवेश लागू होगा। सरकार विद्यार्थियों और उद्योगों के बीच परस्पर संवाद के लिये एक प्लेसमेंट पोर्टल बनाने जा रही है।

79. बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को इस बार लेपटॉप की राशि के स्थान पर लेपटॉप दिए जाएँगे। अगले सत्र से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हिन्दी में प्रश्न-पत्र दे सकेंगे। विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जायेगा। सभी संभाग में एक एक्सीलेंस कॉलेज और जिले में एक मॉडल कॉलेज बनाया जाएगा। विद्यार्थियों से जुड़ी प्रमुख सुविधाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया जायेगा।

80. सरकार छात्रहित में दो नयी योजनाएँ लागू करने जा रही है। पहली योजना में अनाथ बालिकाओं के 12वीं में 60 प्रतिशत अंक आने पर उनके स्नातक स्तर का शिक्षा व्यय सरकार वहन करेगी। दूसरी योजना में चयनित प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति अथवा फीस हेतु आर्थिक सहायता देने की होगी।

81. तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रदेश की प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। तदुपरान्त उन्हें रोजगार या स्वरोजगार में स्थापित करने के प्रयास किये जाएंगे। कौशल और स्वरोजगार को जोड़ते हुए प्रदेश के युवाओं के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन चलाने का निर्णय लिया गया है।

82. मेरी सरकार द्वारा कक्षा 8वीं के बाद दो वर्षीय आईटीआई उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं समतुल्य एवं 10वीं कक्षा के बाद दो वर्षीय आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं कक्षा से समतुल्यता प्रदान की जा रही है।

83. एशियन डेव्हलपमेंट बैंक के सहयोग से 240 मिलियन डॉलर की योजना तैयार की है। योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल संस्थान की स्थापना की जायेगी। इस वर्ष भोपाल में ग्लोबल स्किल समिट में उद्योगों से प्रदेश में Intention to Employ एमओयू किये जायेंगे। साथ ही संभाग स्तरीय 10 आई. टी. आई. को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित किया जायेगा।

84. प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग/ पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा रही है। धार, शिवपुरी एवं सिंगरौली में इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जल प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं। आगर में पोलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

85. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्षेत्र में भारत शासन ने प्रदेश को देश में पाँचवें स्थान पर माना है। अक्टूबर 2016 में इन्दौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 5.62 लाख करोड़ के 2630 इंटेशन टू इन्वेस्ट प्राप्त हुए जिन पर अमल के लिये इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त कर कार्यवाही की जा रही है। रुपये 2632 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को इस वित्त वर्ष में स्वीकृति दी गयी है। इससे 7447 लोगों को रोजगार मिलेगा।

86. सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये औद्योगिक प्रयोजन भूमि के मूल्य में छूट/रियायत का निर्धारण, जीएसटी लागू होने पर भी राज्य की निवेश नीतियों के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को निरंतर रखने और वृहद खाद्य प्र-संस्करण परियोजनाओं के लिये विशेष सुविधा पैकेज देने के फैसले लिये हैं।

87. प्रदेश में 15 नये औद्योगिक क्षेत्र तीन हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 2400 करोड़ की लागत से विकसित किये जा रहे हैं। विद्यमान 13 औद्योगिक क्षेत्रों का 480 करोड़ के खर्च से उन्नयन किया गया है। पीथमपुर में 373 करोड़ की लागत से औद्योगिक टाउनशिप विकसित हो रही है। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन 300 करोड़ से विकसित हो रही है। भारत सरकार द्वारा रायसेन के ग्राम तामोट और ग्वालियर के बिलौआ में प्लास्टिक पार्क स्थापित किये जा रहे हैं। भारत सरकार ने टेक्सटाइल योजना के तहत इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। पीथमपुर जल-प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

88. रोजगार मेलों से इस वर्ष अब तक 53 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। कैरियर काउंसिलिंग का लाभ 54 हजार 456 बेरोजगारों को मिला है।

89. प्रदेश में पिछले वर्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के गठन से प्रदेश में छोटे उद्योगों का जाल बिछाने में मदद मिल रही है। ''मध्यप्रदेश इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016'' लागू की गई है। स्व-रोजगार योजनाओं के आवेदन एवं औद्योगिक भू-आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है। उद्योगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015'' में संशोधन किये गये हैं।

90. इस वित्त वर्ष में अब तक 67 हजार 256 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का उद्योग आधार मेमोरेण्डम के तहत पंजीयन हुआ। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में माह जनवरी, 2017 तक 49646 हितग्राहियों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1446 हितग्राहियों एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 22026 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। अगले वर्ष साढ़े सात लाख लोगों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने का मेरी सरकार का लक्ष्य है।

91. लेदर सेक्टर कौशल विकास केन्द्र की स्थापना शिवपुरी, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं कटनी में की गई है। ग्वालियर में सीपेट का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया है। ग्वालियर में ही 15 करोड़ 72 लाख की लागत से टेक्सटाईल इंक्यूबेशन सेंटर की स्वीकृति मिल गई है। देवास में लेदर इंक्यूबेशन सेंटर माह जनवरी 2017 में स्थापित किया गया है।

92. मेरी सरकार ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2016-17 में दिसम्बर तक मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5434 तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 1947 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

93. चंदेरी व महेश्वर हाथकरघा क्लस्टर में डिजाईन स्टूडियो की स्थापना की जा रही है। परम्परागत ''हाथकरघा/हस्तशिल्प क्लस्टरों'' में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। सरकार ने बैतूल जिले में सतपुड़ा वूमन सिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी का पंजीयन कराया है।

94. मेरी सरकार श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रम कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी है। सरकार ने पन्द्रह कानूनों में मात्र एक पंजी और अभिलेख रखे जाने का तथा मात्र दो वार्षिक रिटर्न का प्रावधान किया है। महिलाओं को कारखानों में रात-पाली में सुरक्षा व्यवस्था सहित कार्य की अनुमति दी गई है। सरकार के औद्योगिक सुरक्षा के प्रयासों से कारखानों में दुर्घटना की दर घटकर 0.49 रह गई है। कारखाना लायसेंस रजिस्ट्रेशन अनुमोदन एवं लायसेंस नवीनीकरण को ऑनलाइन किया गया है।

95. वित्त वर्ष 2016-17 में अब तक पंजीकृत 87 हजार 233 निर्माण श्रमिकों को मिलाकर कुल 24 लाख 90 हजार 384 का पंजीयन किया जा चुका है। निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 675 करोड़ 35 लाख की सहायता दी गई है।

96 प्रदेश के राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया है। राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने के दिन नियत किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में 16 राजस्व सेवाएँ अधिसूचित की गई हैं। व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण को भी इस कानून में सम्मिलित किया गया है।

97. आबादी क्षेत्र में अब तक 14 लाख 25 हजार 32 भू-खण्ड धारकों को प्रमाण-पत्रों का प्रदाय किया गया है। किसानों एवं भू-धारकों की सुविधा के लिए प्रदेश के 32 जिलों में ऑनलाइन वेब जी. आई. एस. लागू किया गया है। शेष जिलों में भी आगामी तीन माह में यह लागू हो जायेगा। सभी तहसील अभिलेखागारों को साइबर रिकार्ड रूम में परिवर्तित किया गया है।

98. नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। इसे प्रदूषणमुक्त बनाने और जल के प्रवाह को अविरल बनाए रखने हेतु ''नमामि देवी नर्मदे'' नर्मदा सेवा यात्रा संचालित की जा रही है। यात्रा के जरिए नर्मदा किनारे के गांवों में नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जागरुक किया जा रहा है। सभी गांवों को खुले में शौच के मुक्त किया जा रहा है, नर्मदा किनारे के सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है, पूजन-हवन सामग्री के लिए पृथक से कुण्ड बनाए जा रहे हैं, घाटों की मरम्मत और चेंजिंग रूम बनाने का कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर तक वृक्ष रोपित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत शासकीय जमीनों पर सरकार द्वारा और निजी जमीनों पर किसानों द्वारा शासकीय अनुदान की मद से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। कृषक की इच्छानुसार फलदार वृक्ष अथवा कृषि वानिकी का कार्य इसमें किया जाएगा। किसानों को अपनी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए न केवल अनुदान दिया जाएगा बल्कि प्रथम तीन वर्ष के लिए जो वे खेती कर रहे थे उसकी प्रतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

99. नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जिन-जिन कार्यों को करने हेतु जागरुकता फैलाई जा रही है। उन सभी का सक्रियता से फॉलोअप करने के लिए नर्मदा सेवा मिशन की शुरूआत मेरी सरकार द्वारा की जा रही है।

100. ''दीनदयाल वनांचल सेवा'' से वनवासियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की सरकार की पहल का लाभ 15 हजार वनवासियों को मिला है। ग्रामीण अंचलों की शालाओं के विद्यार्थियों में वन एवं वन्य-प्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता लाने के ''अनुभूति कार्यक्रम'' से 50 हजार विद्यार्थियों को जोड़ा गया है।

101. मेरी सरकार ने तीन सौ विद्यालयों में रोपणी स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश के नौ शहरों भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर तथा दतिया के समीप स्थित वन क्षेत्रों में अधिकतम 100 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण, औषधीय हर्बल गार्डन आदि कार्य किये जायेंगे।

102. टाइगर रेंज देशों की बैठक में कान्हा टाइगर रिजर्व को सक्रिय प्रबंधन तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट ग्राम विस्थापन एवं पुनर्वास के लिये पुरस्कृत किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 50 से अधिक गाँवों का विस्थापन कर बड़े भू-भाग को जैविक दवाब से मुक्त करवाया गया है।

103. बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विगत दो वर्षों में कुल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकार ने वन्य-प्राणियों द्वारा जनहानि/जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की है। अब जनहानि होने पर रुपये 4 लाख दिये जायेंगे। वन्य-जीव से पशुहानि तथा पशुघायल के प्रकरणों में आर. बी. सी. के प्रावधानों से क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

104. सरकार ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों के रोजड़ों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की शुरुआत की है। मंदसौर जिले में बोमा तकनीक का उपयोग करते हुए 21 रोजड़ों को सुरक्षित गांधी सागर के जंगल में छोड़ा गया है।

105. साल बीज वनोपज को राष्ट्रीयकृत से हटाकर अराष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016 में 18 लाख 56 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहीत कर संग्राहकों को 1250 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से 232 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

106. राज्य बांस मिशन ने समग्र बांस विकास योजना तैयार की है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पौने 2 करोड़ के व्यय से 7000 लोगों को वनोपज आधारित कौशल विकास का लाभ देने का लक्ष्य है।

107. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की एक लाख आठ हजार बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इस साल 5337 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की गई। बड़े ग्रामों में 15 हजार 129 नल-जल योजनाएं संचालित हैं। फ्लोराइड प्रभावित 120 बसाहटों, 552 आंगनवाड़ी और 621 चिन्हित शालाओं में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सभी गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में मार्च 2017 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास है। ''नल से जल, आज और कल'' अभियान में दो लाख से कम राशि में शुरु की जा सकने वाली योजनाओं के लिये पंचायतों को राशि दे दी गई है। दो लाख से अधिक की राशि की योजनाएं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी चालू करेगा। जल निगम 17 जिलों के 768 ग्रामों के लिये 20 समूह जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

108. मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम में सभी जिलों में 500 आंगनवाड़ियों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था पहुंचाने का कार्य करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल के स्तर को बनाये रखने, भू-जल संवर्धन एवं पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा कोष की राशि से वर्ष 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पंप से पेयजल व्यवस्था के कार्य होंगे।

109. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में पांच करोड़ चौंतीस लाख आबादी को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में एक रुपये किलो की दर से खाद्यान्न और नमक तथा 20 रुपये प्रति किलो शक्कर दी जा रही है। इस पर राज्य सरकार वर्ष 2015-2016 हेतु 416.11 करोड़ का अनुदान प्रदान किया है। वर्ष 2016-2017 हेतु रुपये 724.11 करोड़ रुपये की प्रावधान किया गया है। पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना, सभी बीपीएल और 23 अन्य श्रेणी के गैर बीपीएल परिवार शामिल किये गये हैं।

110. लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कम्प्यूटरीकृत की जा रही है। सभी 22 हजार 401 राशन दुकानों पर पीओएस मशीनों से राशन का वितरण हो रहा है।

111. भोपाल, इन्दौर, खण्डवा, देवास, बुरहानपुर एवं छिन्दवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में पात्र परिवार की पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से की जा रही है। इसे अन्य शहरों में भी चरणबद्ध लागू किया जायेगा।

112. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत निर्धन परिवारों की महिलाओं को अभी तक 18 लाख 63 हजार नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इस कार्य में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

113. मेरी सरकार ने वाहन परमिट ऑन लाइन देना प्रारम्भ किया है। इससे सिंहस्थ में उज्जैन आने वाले देश और प्रदेश के यात्रियों को सुविधा हुई। गतवर्ष महिलाओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस देने की योजना में एक लाख 14 हजार 697 लर्निंग और 59 हजार 80 ड्रायविंग लायसेंस दिये गये हैं। नि:शक्तजनों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी गई। पर्यटन वाहनों को दिये जाने वाले अस्थाई परमिट की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया है। प्रदेश में नॉन स्टॉप बस सेवा प्रारम्भ की गई है। प्रदेश को प्रदूषणमुक्त करने की दिशा में ग्रीन टैक्स लगाया गया है।

114. वास्तविक कृषकों के स्वामित्व की ट्रेक्टर ट्राली और हार्वेस्टर को अनुज्ञा-पत्र से मुक्त किया गया है। ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू कर सेवा में पंजीकृत वाहनों को मात्र एक प्रतिशत कर की सुविधा दी गई है। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के ऐसे वाहन मालिकों, जिन्होंने शासकीय योजनाओं में ऋण प्राप्त कर वाहन खरीदे हैं, के वाहनों को पंजीयन से चार वर्ष के लिये वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी है।

115. आनंद विभाग का गठन समाज के सभी वर्गों को परिपूर्ण जीवन जीने की कला सीखने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान का पृथक् से गठन किया जा चुका है। विभाग द्वारा दिनांक 14 से 21 जनवरी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7500 स्थलों पर आनंद उत्सव का आयोजन किया गया. ''आनंदम'' कार्यक्रम जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों की सहायता करने से आनंद का अनुभव होगा, भी शुरू किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में आनंद सभाएं और शासकीय कार्यालयों में अल्प विराम कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है।

116. प्रदेश में वर्तमान में 33 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षापेंशन योजनाओं का भुगतान ई-पेमेंट से किया जा रहा है। मेरी सरकार ने इस वर्ष पेंशन राशि को 150 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ साढ़े तीन लाख कन्याओं और निकाह योजना का लाभ अब तक 8 हजार 617 कन्याओं को मिला है। योजना का लाभ लेने वाली कन्याओं को स्मार्ट फोन दिये जाने का फैसला भी हमने लिया है।

117. दिव्यांग दंपत्तियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लाभ के अलावा 50-50 हजार की सहायता दी जा रही है। इस वर्ष 178 दृष्टि और 230 अस्थि-बाधित दिव्यांगों को आईटीआई में प्रवेश दिलाया गया। रोजगार मेले के जरिये 400 विकलांगों को रोजगार दिलाया गया। अगले वर्ष से 41 जिलों में दृष्टि बाधित, मूक-बधिर एवं मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांगों के लिये मिडिल स्कूल खुलेंगे।

118. मध्यप्रदेश स्टेट पेंशन पोर्टल को भारत सरकार का नेशनल ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

पुनर्वासन सेवाओं के लिये जबलपुर और झाबुआ जिले को तथा सर्वश्रेष्ठ बाधा रहित वातावरण की श्रेणी में इन्दौर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

119. मेरी सरकार प्रदेश को देश के खेल मानचित्र पर स्थान दिलाने में सफल रही है। बीते एक साल में प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 35, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 224 तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 242 पदक अर्जित किये हैं। महिला हॉकी अकादमी को हॉकी इंडिया ने प्रेसीडेन्ट अवार्ड से सम्मानित किया है।

120. इस वर्ष भोपाल में नयी एथलेटिक्स और होशंगाबाद में एक्वाटिक्स एवं ट्रायथलान अकादमी प्रारंभ की गई। ग्वालियर में एक अतिरिक्त हॉकी टर्फ और इन्दौर, शिवपुरी, मंदसौर, होशंगाबाद और दमोह में सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ की स्वीकृति दी गई है। भोपाल में बिशनखेड़ी शूटिंग रेंज बन गयी है। खेलों के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कप और विधायक कप का आयोजन निरंतर है।

121. मेरी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कैबिनेट का गठन किया है। पर्यटन नीति 2016 लागू कर दी गई है। प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने की पुनः पहल कर अनुबंध किया जा चुका है। ओंकारेश्वर को केन्द्र की ''प्रसाद'' योजना में शामिल करवाने की पहल की गयी है। रामायणा सर्किट के विकास की कार्यवाही प्रचलित है। नाधोगढ़ फोर्ट, सतना, गोविन्दगढ़ पैलेस रीवा तथा ताजमहल पैलेस भोपाल को नई हेरिटेज पॉलिसी में निवेशकों के सहयोग से विकसित किया जायेगा।

122. भारत सरकार से रुपये 92 करोड़ से ज्यादा की वाइल्ड लाइफ, रुपये 75 करोड़ की बुद्धिस्ट और रुपये 99 करोड़ की हेरीटेज सर्किट परियोजना की मंजूरी मिली है। पर्यटन से रोजगार सृजन योजना पर अमल हो रहा है।

123. खण्डवा जिले के हनुवंतिया में एक माह का द्वितीय जल-महोत्सव सफल रहा है। महोत्सव के दौरान 5 लाख पर्यटक आए। हनुवंतिया में दो हाउस बोट के जलावतरण से प्रदेश हाउस बोट संचालन वाले राज्यों में शामिल हो गया है। लगभग 238 हेक्टेयर में हनुवंतिया विस्तार योजना तैयार की गई है। प्रदेश के अन्य वृहद जल संरचनाएं जैसे गांधी सागर, बाणसागर, बरगी और तवा जलाशयों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आगे योजना है।

124. मेरी सरकार के प्रयासों से कला-संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान बनी है। इस पहचान में नया नाम है भोपाल में पिछले साल स्थापित शौर्य स्मारक का। सरकार प्रतिवर्ष ढाई सौ, तौन सौ सांस्कृतिक आयोजन-समारोह करती है। खण्डवा, सागर और रीवा में आंचलिक कला संकुल स्थापित होंगे। भोपाल के रविन्द्र भवन का उन्नयन किया जा रहा है।

125. मेरी सरकार द्वारा ओरछा-ग्यालियर सर्किट, बुरहानपुर-इन्दौर सर्किट, भोपाल एवं विंध्य-जबलपुर सर्किट के 292 स्मारक के अनुरक्षण एवं विकास कार्य किये जा रहे हैं। संस्कृति विभाग और वर्ल्ड मान्यूमेंट फण्ड के मध्य हुए करारनामे के अनुसार 54 स्मारकों के अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। महिदपुर किले के अनुरक्षण को यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है।

126. मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ इस वर्ष एक लाख 2 हजार वरिष्ठ नागरिकों ने लिया है। योजना में इस साल पटना साहिब, गंगासागर और प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों को शामिल किया गया है।

127. मेरी सरकार देश की पहली सरकार है जिसने अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में नागरिकों को प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी है। हमारे बाद बीस अन्य राज्यों ने भी ऐसे कानून बनाये हैं। अब भारत सरकार भी इस तरह का कानून बना रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक 28 विभागों की 207 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं, जिनमें से 140 सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहा रहे हैं। कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये मेरी सरकार ने अलग से ''लोक सेवा प्रबंधन विभाग'' एवं ''राज्य लोक सेवा अभिकरण'' का गठन किया है। कानून के अमल में आने के बाद अब तक 4 करोड़ 15 लाख आवेदन का निराकरण कर नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से ऑनलाईन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश के समस्त ब्लाक एवं तहसील स्तर पर कुल 413 लोक सेवा केन्द्र एवं लगभग 6,000 से अधिक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क संचालित किये जा रहे हैं।

128. मेरी सरकार ने स्व-घोषणा के आधार पर स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था की है। शपथ-पत्र की जगह स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र पर सेवाओं का प्रदाय किया जा रहा है।

129. स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान देने के अभियान में अब तक सवा करोड़ डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं। अभियान की तिथि 30 जून 2017 तक बढ़ा दी गई है।

130. मेरी सरकार ने जनशिकायत निवारण की संस्थागत व्यवस्था की है। समाधान ऑनलाईन में प्राप्त चयनित शिकायतों का मुख्यमंत्रीजी द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग से आवेदक की उपस्थिति में निराकरण किया जाता है। कार्यक्रम में निराकरण का प्रतिशत 94 है।

131. मेरी सरकार द्वारा सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स का प्रभावी यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आम जनता एवं व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट की महत्ता तथा डिजिटल संव्यवहार के लिये जागरूक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में आई.टी. पार्कों की स्थापना की जा रही है।

132. सरकार ने परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था की है। रोजगार के नये अवसरों के लिये आई.टी., आईटीइएस एण्ड ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 और एनॉलाग सेमीकन्डक्टर फैब निवेश नीति लागू की गई है। जबलपुर में ई.आई.सी.टी. अकादमी की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायतों तक इन्टरनेट की सुविधा हेतु तेजी से जरूरी अधोसंरचना स्थापित की जा रही है।

133. मेरी सरकार ने कर्मचारी कल्याण को नये आयाम दिये हैं। इस वर्ष कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, समयमान वेतनमान एवं स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, जो पहले नहीं थी। नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगियों को ''स्थायी कर्मी'' की श्रेणी दी गई है। इन्हें अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी अनुसार वेतनमान/वार्षिक वेतन वृद्धि/ मंहगाई भत्ता/उपादान की सुविधा भी दी गई है। इससे लगभग 48,000 कर्मचारी लाभांवित होंगे।

134. सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि 15 हाजर से बढ़ाकर 25 हजार और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है।

135. मेरी सरकार प्रदेशवासियों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस वर्ष प्रदेश में अपर जिला न्यायाधीश के 231 पद स्वीकृत किये गये हैं। इनमें जबलपुर, इन्दौर, भोपाल और ग्वालियर में स्थापित न्यायालय सायबर और उच्च तकनीकी अपराधों के लिये है। जिला न्यायालय भवनों के लिये 149 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

जजों और कर्मचारियों के आवास गृहों के लिये 110 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।

136. मेरी सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर रखने में सफलता मिली है। सरकार ने नक्सली और दस्यु समस्या के उन्मूलन के साथ सिमी की गतिविधियों पर नियंत्रण किया है। इस साल सभी त्यौहार सौहार्द से मनाये गये। उज्जैन सिंहस्थ में पुलिस व्यवस्था की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। दस साल में पुलिस बल में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। होमलैण्ड सिक्योरिटी के लिये 136 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। अब 10 हजार पुलिसकर्मियों के सर्वसुविधायुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदेश में है। पुलिस आधुनिकीकरण की 45 योजनाओं पर प्रतिवर्ष 1000 करोड़ की राशि के व्यय से प्रदेश देश में अग्रणी है।

137. अपराधों पर नियंत्रण के लिये समय-समय पर संचालित विशेष अभियानों को सफलता मिली है। दो लाख से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट तामील करवाये गये हैं। लम्बे समय से फरार 33 हजार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में दर्ज अपराधों में चालान का प्रतिशत 93.3 है, जो केरल के बाद देश में सर्वाधिक है।

गंभीर अपराधों को चिन्हित कर जिला, संभाग एवं प्रदेश स्तरीय मानिटरिंग की जा रही है। गुमशुदा बच्चों की खोज के लिये आपरेशन मुस्कान और स्माइल चालये गये हैं बीट प्रणाली को मजबूत बनाया गया है। पुलिस-जन संवाद आयोजित किये जा रहे हैं।

138. मेरी सरकार महिला अपराधों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सभी जिलों में महिला अपराध प्रकोष्ठ गठित हैं। शिकायतों की जल्द सुनवाई के लिए 141 महिला डेस्क स्थापित की गई हैं। राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 पर दिसम्बर तक प्राप्त 21 हजार 222 शिकायतों का समाधान किया गया है। कन्या महाविद्यालयों में संवाद शिविर का आयोजन निरंतर है। सभी जिलों में महिला अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किये गये हैं।

139. डायल 100 योजना को 17 अन्य राज्य ने अपनाया है। योजना के एक हजार वाहन पूरे प्रदेश में गतिमान है। योजना को उन्नत कर स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेन्टर के रूप में स्थापित करने की कार्य-योजना बनायी जा रही है। बड़े 61 शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों और चौराहों पर सीसीटीवी लगाये जा रहे हैं।

थानों में सी.सी.टी.वी. निगरानी व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है। एक हजार से अधिक थानों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें ऑनलाइन किया गया है।

140. प्रदेश में वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में 35.50 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 46. 62 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2015 में महिला अपराधों में 15.84 और बच्चों के विरूद्ध अपराधों में 14.76 प्रतिशत की कमी आई है।

141. प्रदेश में 82 नवीन थाने, 133 चौकियाँ तथा 13 पर्यटन चौकियाँ स्थापित की गई हैं। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कर 02नवीन वाहिनियाँ जिला सिंगरौली एवं रीवा में स्थापित की गई। बालाघाट में भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया गया है। सभी जिलों में अजाक थाने खुल गये हैं।

142. पुलिसकर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी गई है। हुडको के ऋण से चार चरण में 10 हजार 500 आवास निर्माणाधीन हैं। आगामी वर्षो में भी आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आवासों की मरम्मत पर भी सालाना 50 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पुलिसकर्मी और उनके आश्रितों को 8 लाख तक की सहायता दी जा रही है।

143. मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालने हेतु पूरे प्रयास किए हैं। हमें अपने लक्ष्य में सफलताएं मिली हैं परंतु विकसित देशों की भांति मध्यप्रदेश के नागरिकों की जीवन शैली हो, इस हेतु अनेक गुरूतर प्रयास अभी लगेंगे। युग-पुरूष अटलबिहारी बांजपेयी जी के शष्दों में—

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुष्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ,
असफल सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।

जय हिन्द, धन्यवाद।